सुभाषित यदि किसी देशको भ्रष्टाचारमुक्त और सुंदर मनवाले लोगोंका देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाजके तीन प्रमुख सदस्य यह कार्य कर सकते हैं-माता-पिता और गुरु। ❒ एपीजे अब्दुल कलाम

युद्ध समाधान नहीं

विगत छह माहसे अधिक समयसे जारी रूस-यूक्रेन युद्ध थमनेका नाम नहीं ले रहा है। यह सदीका सबसे लम्बा चलनेवाला युद्ध बनता जा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव पूरी दुनियापर पड़ रहा है। २४ फरवरी, २०२२ से शुरू युद्धके चलते पूरा विश्व दो गुटोंमें बंट गया है। यह युद्ध कब समाप्त होगा, यह अनिश्चित है। रूस-यूक्रेन युद्धके सन्दर्भमें प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीने बुधवारको एक महत्वपूर्ण बयान दिया है जिसपर दोनों देशों और उनके मित्र राष्ट्रोंको गम्भीरतासे सोचनेकी आवश्यकता है। रूसके सुदूर पूर्वमें स्थित ब्लादिवोस्तोक शहरमें आयोजित सातवें ईस्टर्न इकोनामिक फोरमको वर्चुअल रूपसे सम्बोधित करते हुए प्रधान मंत्री मोदीने कहा कि रूस-यूक्रेन विवादको बातचीतसे सुलझाया जाना चाहिए। संघर्षकी शुरुआतसे ही हमने वार्ता और कूटनीतिका मार्ग अपनानेकी आवश्यकतापर जोर दिया है। हम इस संघर्षको समाप्त करनेके लिए सभी शान्तिपूर्ण प्रयासोंका समर्थन करते हैं। आजके वैश्वीकृत दुनियामें किसी एक हिस्सेकी घटनाएं पूरे विश्वको प्रभावित करती हैं। यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारीसे वैश्विक आपूर्ति व्यवस्थापर काफी प्रभाव पड़ा है। खाद्यान्न, उर्वरक और ईंधनकी कमी विकासशील देशोंके लिए बड़ी चिन्ताका विषय है। प्रधान मंत्री मोदीने अपने सम्बोधनमें तमाम मुद्दोंपर भारतके पक्षको रखा लेकिन रूस-यूक्रेन युद्धके सन्दर्भमें उनका वक्तव्य महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। इस युद्धका समाप्त होना न केवल दो देशोंके लिए अपितु पूरे विश्वके हितमें है। युद्धसे यूक्रेनमें जहां भारी तबाही हुई है वहीं रूसको भी भारी क्षति उठानी पड़ी है। दोनों पक्षोंको जान-मालकी भारी क्षति पहुंची है। यदि युद्ध और लम्बा खिंचता है तो इससे तबाही और बढ़ेगी। ऐसी स्थितिमें यह आवश्यक है कि कूटनीति और वार्ताके माध्यमसे युद्धको समाप्त करानेके लिए वैश्विक स्तरपर ठोस प्रयास किये जाय, क्योंकि युद्ध किसी विवादका समाधान नहीं हो सकता है।

राज्योंको हिदायत

रद की जा चुकी आईटी ऐक्टकी धारा ६६-ए के तहत एफआईआर दर्ज किये जानेपर सर्वोच्च न्यायालयने गम्भीर रुख अपनाते हुए जनहितके पक्षमें बड़ा फैसला सुनाया है। इससे उन लोगोंको फायदा होगा जिनको आईटी ऐक्टके तहत जेलमें बंद कर दिया जाता है। विचार और अभिव्यक्तिकी आजादीको मौलिक अधिकार देते हुए सर्वोच्च न्यायालयने २४ मार्च २०१५ को आईटी ऐक्टकी धारा ६६-ए को रद कर दिया था, लेकिन अब भी उसके तहत जिस तरह लोगोंकी गिरफ्तारी की जा रही है, वह न्यायालयकी अवमानना है, सरकारोंको इसपर जहां गम्भीरतासे सोचनेकी जरूरत है, वहीं स्मार्टफोनके उपभोक्ताओंका दायित्व बनता है कि वह ऐसा कोई पोस्ट न करें जिससे दूसरेकी भावना आहत होती हो। अभिव्यक्तिकी आजादी हमारे संविधानने दी है, लेकिन उसके पालनके लिए कुछ कर्तव्य बनाये हैं जिनका अनुपालन समाजमें सामंजस्यके लिए जरूरी है। गैर-सरकारी संघटन पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज सहित विभिन्न संघटनोंकी याचिकाओंकी सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश यूयू ललितकी अध्यक्षतावाली पीठने इसपर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हुए आईटी ऐक्टकी धारा ६६-ए के तहत दर्ज मामलोंको वापस लेनेका आदेश देकर सरकारोंको सख्त सन्देश दिया है। इस धाराके तहत इण्टरनेटपर आपत्तिजनक पोस्ट करनेपर तीन सालकी कैदकी सजा और जुर्मानेका प्रावधान है जिसे रद किया जा चुका है लेकिन विभिन्न राज्य सरकारें इसका दुरुपयोग कर रही हैं, जो न्यायकी अवधारणाके विपरीत है। सरकारोंको सर्वोच्च न्यायालयकी भावनाका सम्मान करते हुए आईटी ऐक्टकी ६६-ए का प्रयोग पूरी तरह बंद करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालयका फैसला उचित है, इसका अनुपालन किया जाना चाहिए।

लोक संवाद

फिसलनकी प्रवृत्ति

महोदय,- हर जगह कुछ ऐसे खास किसिमके महानुभाव होते हैं जो अपने ईमान, जुबानकी परवाह किये बिना दूसरोंके ईमान, जुबानके फिसलनेकी फिराकमें चौबीसों घंटे मुस्तैद रहते हैं सोये-सोये भी। वे अपने ईमान, जुबानसे बेपरवाह किसीके भी ईमान, जुबानकी फिसलनको फिसलन मापी यंत्र लिये पल-पल मापते रहते हैं। ज्यों ही उन्हें किसीके ईमान, जुबानका अपने फिसलन मापी यंत्रमें स्तर सामान्यसे ऊपर नजर आता है तुरंत वे चौकन्ने हो जाते हैं। तब और जगह किसीके फिसलनेपर हंगामा हो या नयेपर राजनीतिमें हंगामा जरूर होता है, खूब होता है। तबतक होता है जबतक अगले हंगामेके आसार नहीं दिखते। हंगामेका पर्याय राजनीति है। हंगामेके बिन राजनीति बेजान होती है। फिसलनेके पीछे सौ बहाने होते हैं तो फिसलनपर हंगामा करनेके हजार। जिस बयानपर उबाल न उठे वह बयान मेरे दूधवालेके दूध-सा होता है। अब मेरे दूधके पतीलेमें दूध गरम करते हुए उबाल नहीं आता, परन्तु राजनीतिके पतीलेमें इनके उनके ईमान, जुबान आये दिन उबाल लाये रहते हैं। ऐसेमें कह सकता हूं कि मेरे पतीलेमें न सही, उनके पतीलेमें ही सही, हो कहीं भी बवाल, उबाल आना चाहिए। राजनीति और जिंदगीकी सड़क पगडंडियोंपर पता नहीं कौन सज्जन कब जैसे किसीके ईमान, जुबानकी राहमें केले खाकर छिलके फेंक दे और हंसता हुआ दुम दबाकर कोनेमें उसके फिसलनेका बेसब्रीसे इंतजार करता रहे और बंदा जब सीना तान अपने ईमान और जुबानपर लगाम लगाये बाहर निकले तो धड़ामसे फिसल जाय। अपने यहां कोई चरित्रसे फिसलता है तो कोई जुबानसे। कोई ईमानसे फिसलता है तो कोई सत्कामसे। बहुत कम ऐसे होते हैं जो मजबूरीमें मेहनत मशक्कतके बाद फिसलते हैं। धन्य हैं वे जो बड़े आरामसे कदम-कदमपर फिसलते हैं। ऐसे बड़े जीव भाग्यशाली होते हैं। इनका अवतरण फिसलनेके लिए ही हुआ होता है। फिसले हुए को समाज हाथों हाथ उठाता है। उनकी आरती उतारता है। ईमान और जुबानसे फिसलनेके बाद जब एक-दूसरेके फिसलनेकी ताकमें बैठे हुए को पता चलता है कि भाई साहब! फलां फिसल लिया तो देखते ही देखते शुरू उबाल हंगामा। बात-बातपर उबाल, हंगामे, बंदके सिवाय और हमें चाहिए भी क्या! रोटी कपड़ा मकानकी जरूरत आज है भी किसे। दूसरी ओर फिसलनेसे उबाल उठनेके बाद शानसे मांग ली माफी। साहब! गलतीसे ईमानसे, जुबानसे फिसल गया था। ईमान, जुबानसे फिसलनेका मेरा इरादा कतई न था और आ गये वालोंकी मुख्यधारामें। वैसे इन दिनों फिसलकर और ऊंचे उठनेका प्रचलन जोरोंपर हैं। बिन उबाल, हड़ताल, हंगामे, बंदके आज जीवन और राजनीति बिन सिंदूरके लगती है। राजनीतिमें मरा सांप मारा नहीं जाता। उसे घायल कर छोड़ दिया जाता है। हवामें उसपर तड़ातड़ लाठियां बरसायी जाती हैं। राजनीतिमें सांप मर जाय तो लट्ठाधीशोंका फ्यूचर क्या हो। बयानोंके मोर्चोंपर दिन-रात तैनात रहनेवालोंका क्या हो। इन दिनों सबसे ज्यादा जो कोई ईमान और जुबानसे आजकल फिसलने लगे हैं तो वे वेजी हैं। वे बात-बातपर ही कहीं जहां फिसलनेकी रत्तीभर भी गुंजाइश न हो वहां भी जुबान, ईमानसे फिसल जाते हैं। इनके ईमान और जुबानका फिसलना जैसे अब उनके वशमें भी नहीं। ईमान, जुबानसे फिसलना ज्यों इनकी राजनीतिक मजबूरी हो। मजबूरी जीवको कहां-कहां नहीं फिसलवाती भाई साहब! वैसे ईमान और जुबान किसीके बसमें कब रहे हैं भला। कई बार तो ईमान, जुबानकी फिसलनको देखकर लगता है कि ज्यों जीवको भगवानने ईमान और जुबान दिये ही फिसलनेके लिये हों। **-अशोक गौतम, वाया ईमेल।**

चुनौतीपूर्ण होगा ट्रसका शासन

भारतीय ऋषि सुनक ब्रिटेनके प्रधान मंत्री होनेसे चूक गये। फिर भी उन्हें अपने प्रतिद्वन्दी लिज ट्रसके ५७ प्रतिशत मतोंके मुकाबले ४२ प्रतिशत वोट मिला। ऋषि सुनक कंजर्वेटिक पार्टीके नेता पदका चुनाव हारे जरूर किन्तु उन्होंने अपनेको एक विश्वसनीय और योग्य नेताके रूपमें स्थापित कर लिया है।

❒ विजयनारायण

सन् १८९२ में दादाभाई नारोजी पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद यानी हाउस आफ कामंसके लिए चुने जानेवाले पहले भारतीय थे। तब एक इतिहासकी रचना हुई थी। एक और भारतीय ऋषि सुनक ब्रिटेनका प्रधान मंत्री होनेसे चूक गये। फिर भी उन्हें अपने प्रतिद्वन्दी लिज ट्रसके ५७ प्रतिशत मतोंके मुकाबले ४२ प्रतिशत वोट मिला। ऋषि सुनक कंजर्वेटिक पार्टीके नेता पदका चुनाव हारे जरूर किन्तु उन्होंने अपनेको एक विश्वसनीय और योग्य नेताके रूपमें स्थापित कर लिया है। वह हारे जरूर हैं किन्तु जिस तरह वह इतिहास बनानेसे रह गये हैं, उसकी चर्चा और सारी दुनियामें हो रही है। ऋषि सुनकको कंजर्वेटिव पार्टीके कुल सदस्योंमें ४२ प्रतिशत मत प्राप्त करना भी किसी आश्चर्यसे कम नहीं है। ब्रिटेनमें नस्ली प्रभाव पहले काफी कम हुआ है किन्तु आज भी समाप्त नहीं हुआ है। कंजर्वेटिव पार्टीके सांसदोंके बीचसे यदि नेता पदका चुनाव हुआ होता तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था। कंजर्वेटिव पार्टीमें संसदीय दलके नेता चुने जानेकी परम्परा भी अजीब है और काफी हदतक रूढ़िवादी है। इस्तीफा देनेवाला या अवकाश लेनेवाला नेता अपना उत्तराधिकारी स्वयं ही घोषित कर देता है और उसे मान लिया जाता है। १९५२ में प्रधान मंत्री पदसे त्यागपत्र देनेके बाद मैकमिलनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और वहीं अगले प्रधान मंत्री भी बने थे।

ऋषि सुनकको लिज ट्रसकी सरकारमें कोई जिम्मेदारी मिलती है तो किस विभागकी। वैसे ऋषि जानसन सरकारमें मंत्री रह चुके हैं। ब्रिटेनमें बसे भारतीयोंका प्रभाव राजनीतिके साथ सरकारपर भी बढ़ा है। फिर भी भारतके लिए चिन्ताकी बात यह है कि कंजर्वेटिव एवं लेबर पार्टियोंमें भी भारत विरोधी एक गुट सक्रिय रहता है। वर्तमान समयमें लेबर पार्टीके नेता ही भारत विरोधी हैं और शायद यही कारण है कि भारतीय मतदाताओंका रुझान कंजर्वेटिव पार्टीकी तरफ बढ़ा है। ब्रिटेनकी नयी सरकारका सम्बन्ध भारतके साथ कैसा बनता है, यह देखनेकी बात होगी।

इस बार ब्रिटेनके निवर्तमान प्रधान मंत्री जानसनके साथ जो घटनाक्रम चल उसमें उन्हें प्रधान मंत्री पदसे त्यागपत्र देना पड़ा। वास्तवमें उन्होंने पार्टी सांसदोंका विश्वास खो दिया था। इसलिए उन्होंने उत्तराधिकारी चुननेका अधिकारी ही खो दिया था। कंजर्वेटिव पार्टीके नियमोंके अनुसार जब कोई निवर्तमान प्रधान मंत्री या नेता अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करता तो ऐसी स्थितिमें पार्टीके सभी सदस्य संसदीय दलके नेताका चुनाव करते हैं। इस बार हुआ भी यही। कंजर्वेटिव पार्टीके कुल सदस्य संख्या १.८० लाख है और इसमेंसे ९२ प्रतिशत लोगोंने मत दिया था। इस चुनावमें जीतीं लिज ट्रस ब्रिटेनकी तीसरी महिला प्रधान मंत्री होगी। नेता पदके इस चुनावमें लिज ट्रसने कुछ ऐसी लोक-लुभावनी घोषणाएं की हैं, जिसे पूरा करना उनके लिए कठिन है। उन्होंने बिजली बिलोंमें कमी लाने एवं करोंमें कटौती करनेकी बात कही है, जो आजकी वैश्विक आर्थिक स्थितिमें बहुत कठिन लगती है। दूसरी ओर ऋषि सुनक अपने चुनाव घोषणामें आर्थिक स्थितिकी सचाईपर खड़े रहे और शायद वह लोक-लुभावन वायदोंसे बचते रहे। फिर भी उन्हें ४३ प्रतिशत मत मिलना किसी आश्चर्यसे कम नहीं है।

अब देखना यह है कि ऋषि सुनकको लिज ट्रसकी सरकारमें कोई जिम्मेदारी मिलती है या नहीं और मिलती है तो किस विभागकी। वैसे ऋषि सुनक जानसन सरकारमें भी मंत्री रह चुके हैं और जानसनकी कार्यपद्धतिके विरोधमें उन्होंने मंत्री पदसे त्यागपत्र दे दिया था। कुछ लोगोंने जानसनका साथ छोड़नेके लिए उनकी आलोचना भी की थी, लेकिन एक अच्छे और स्पष्टवादी मंत्रीके रूपमें उन्होंने अपनी छाव भी जरूर छोड़ी थी। इंग्लैण्डमें लोकतंत्रका इतिहास वैसे पांच सौ साल पुराना है और ब्रिटिश राजनीतिमें परम्पराएं ही हावी रही हैं। इसीलिए ब्रिटेनमें लिखित संविधान बनानेकी जरूरत महसूस नहीं की गयी। यद्यपि महिलाओंको बराबरीका अधिकार देनेवाला ब्रिटेन पहला देश है किन्तु किसी महिलाको प्रधान मंत्री चुननेमें इस देशके लोगोंने पांच सौ साल लगा दिये। १९७९ में मार्गरेट थैचर ब्रिटेनकी पहली महिला प्रधान मंत्री चुनी गयी थीं और बड़ी प्रभावशाली ढंसे उन्होंने १२ वर्षोंतक चलायी। मैडम टेरी जा दूसरी प्रधान मंत्री बनी थीं किन्तु वह उतना प्रभाव नहीं छोड़ पायीं। लिज ट्रस अब तीसरी महिला प्रधान मंत्री बनी हैं।

लिज ट्रस ऐसी स्थितिमें प्रधान मंत्री बनने जा रही हैं, जब पूरा यूरोप यूक्रेनपर रूसी हमलेके संकटसे जूझ रहा है। पूरे यूरोपके लिए यह संकट राजनीतिक भी है और आर्थिक भी। ब्रिटेन कैसे अपनी नाटोका सदस्य बना हुआ है किन्तू यूरोपीय यूनियनसे वह अलग हो चुका है। यद्यपि ब्रिटेनके विकास दरमें कोई गिरावट नहीं आयी है किन्तु यूरोपीय यूनियनके सदस्य देशोंके साथ उसे नये सिरेसे आर्थिक सम्बन्धोंके आधार निर्धारित करने पड़ रहे हैं। ब्रिटेनकी यूरोपीय देशोंके साथ चल रही बातचीत अब भी समाप्त नहीं हुई है। अब देखनेकी बात यह होगी कि लिज ट्रस सरकार इस स्थितिका समाधान कैसे निकालती है। इस सम्बन्धमें यह जान लेना भी जरूरी है कि ब्रिटेनमें बसे भारतीय समाजने अपने परिश्रम और मेहनतके बलपर ब्रिटिश समाजमें अपनी विश्वसनीयता बढ़ायी है। हाउस आफ कामंसके गत चुनावमें कुल बारह भारतीय जीतकर आये थे और उसमें तीन जानसन सरकारमें मंत्री बने थे। परम्परागत रूपसे भारतीयोंकी रुझान लेबर पार्टीके पक्षमें रहती है किन्तु इस बार कंजर्वेटिव पार्टीके टिकटपर भी कई सदस्य जीतकर आये हैं।

ब्रिटेनमें बसे भारतीय समाजका प्रभाव राजनीतिके साथ ही सरकारपर भी बढ़ा है। फिर भी भारतके लिए चिन्ताकी बात यह बनी रहती है कि कंजर्वेटिव एवं लेबर पार्टियोंमें भी भारत विरोधी एक गुट सक्रिय रहता है। वर्तमान समयमें लेबर पार्टीके नेता ही खुलकर भारत विरोधी हैं और शायद यही कारण है कि भारतीय मतदाताओंका रुझान कंजर्वेटिव पार्टीकी तरफ बढ़ा है। ब्रिटेनकी नयी सरकारका सम्बन्ध भारतके साथ कैसा बनता है, यह देखनेकी बात होगी। जानसन सरकारका रुख बराबर अस्थिर और बदलता रहा है। परन्तु लिज ट्रसको यह समझना चाहिए कि भारतकी आज वह स्थिति नहीं है जो बीस साल या पचास साल पूर्व थी।

हालमें ही वैश्विक अर्थव्यवस्थामें भारत ब्रिटेनको पछाड़ क पांचवे स्थानपर पहुंच गया है फिर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था आज भी भारतसे काफी सुदृढ़ है। भारतपर आबादीका बोझ १४० करोड़ लोगोंका है जबकि ब्रिटेनपर मात्र १२ करोड़ लोगोंका ही है। अच्छी बात यह है कि ब्रिटेन अब भी भारतीयोंको नौकरीके लिए वीजा दे रहा है और लोगोंको स्थायी नागरिकता भी प्रदान कर रहा है किन्तु यह गति पहलेसे काफी धीमी पड़ गयी है। ब्रिटेनकी नयी सरकारपर भारतको इस बातके लिए दबाव बढ़ाना चाहिए कि ब्रिटेनमें नौकरीके लिए जानेवाले भारतीयोंकी संख्या बढ़ायी जाय। लिज ट्रस पूर्व प्रधान मंत्री जानसनकी तरह ढुलमुल रवैया अपनाती हैं या स्पष्टताके साथ अपना मार्ग निर्धारित करती हैं।

आदर्श स्थितिसे विमुख दवा उद्योग

दवा उद्योग और देशके सामने खुराक संबंधी अनेक जटिल समस्याएं हैं, जिनमेंसे कई ऐसी खुराकें बेचते हैं, जो वैश्विक बाजारमें प्रतिबंधित हैं। यह स्थिति नियंत्रणसे बाहर हो चुकी है, विशेष रूपसे ब्रांडेड जेनेरिक दवाओंके मामलेमें।

❒ जगदीश रत्नानी

यह कोई रहस्य नहीं है कि दवा उद्योगने डाक्टरोंको दवा लिखने या मेडिकल सामान देनेके बदलेमें इंसेंटिव देनेके चलनसे बिक्रीसे जुड़ी एक समस्या खड़ी कर दी है। स्वास्थ्य क्षेत्रकी कम्पनियोंने डाक्टरों और अस्पतालोंको घूस देकर अपने उत्पादोंकी बिक्रीका एक पूरा तंत्र ही बना दिया है। यह एक विकृत खेल है, जिससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति पाक-साफ नहीं है। चिकित्सा क्षेत्रके थोड़ेसे लोगोंने इसके खिलाफ आवाज उठायी है, लेकिन इससे गहरी पैठ बना चुके तंत्रको रोका नहीं जा सका है। इस खेलमें भारतीय कम्पनियोंके साथ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी शामिल हैं। इसे अब गलत भी नहीं माना जाता, जबकि यह बेहद खराब चलन है। इस घातक एवं भ्रष्ट खेलमें साधारण भारतीय मरीजोंको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यह तंत्र काम कैसे करता है, इसका विवरण मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव संघटनोंके समूह और अन्यों द्वारा सर्वोच्च न्यायालयमें दायर याचिकामें दिया गया है। इसके शुरूमें कहा गया है कि दवा क्षेत्रमें भ्रष्टाचारसे स्वास्थ्य संबंधी सकारात्मक परिणामोंको खतरोंके कई उदाहरण हैं। डाक्टरों और अन्य चिकित्सा पेशेवरोंको फायदा या घूस देकर गैरजरूरी दवाएं देनेसे मरीजका स्वास्थ्य खतरेमें पड़ जाता है। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्नाकी खंडपीठ द्वारा इस याचिकाको स्वीकार करने तथा सरकारको अपना पक्ष रखनेके लिए कहनेके बाद यह मुद्दा सुर्खियोंमें है।

याचिकामें मांग की गयी है कि दवा कम्पनियों द्वारा डाक्टरोंको उपहार देने और अपना प्रचार करनेके बारेमें वैधानिक नियम बनाये जाने चाहिए। इस सुनवाईने डोलो नामक दवाकी भारी बिक्रीको सामने लाया है। यह दवा ६५० एमजीकी खुराकमें आती है, जबकि अमूमन टैबलेटकी मात्रा ५०० एमजी होती है। कोरोना महामारीके दौरमें इसकी बिक्रीने आसमान छू लिया था। इसके निर्माताके वेबसाइटपर प्रशंसासे भरी मीडिया रिपोर्टोंको लगाया गया है। कम्पनीने अत्यधिक प्रचार और मूल्य नियंत्रणके नियमोंसे बचनेके लिए खुराक बदलनेके आरोपोंका खंडन किया है। याचिका और मुद्देसे जुड़ी आम बहसमें बुनियादी बात यह है कि क्या दवा उद्योगने जनवरी, २०१५ में बने कोडके तहत स्व-नियमनके लिए समुचित कदम उठाये हैं या नहीं। दूसरी बात यह है कि इसमें उद्योगके अनैतिक आचरणको रोकनेकी मांग की गयी है। उक्त कोडमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिवोंके व्यवहार तथा प्रचार, उपहार, नगदी देने जैसे आचरणोंके बारेमें निर्देश हैं, लेकिन इन नियमोंको कानूनके सहारे लागू नहीं कराया जा सकता है। ये केवल निर्देश हैं। यह दिलचस्प है कि ऐसा लगता है कि सरकार अपने पहलेके दृष्टिकोणसे पीछे हट गयी है। पहले उसका विचार था कि इस कोडको अनिवार्य कर देना चाहिए। वर्ष २०२० में सरकारने संसदको बताया था कि अनैतिक आचरणसे संबंधित शिकायतोंकी सुनवाईके लिए विभागके पास कोई प्रावधान नहीं है तथा इस मसलेको दवा संघटनोंकी एक नैतिक समिति द्वारा देखा जाना चाहिए। अपनी इच्छासे किये जानेवाले उपायोंने कदाचारको रोकनेमें कोई खास कारगर भूमिका नहीं निभायी है। एक भयावह महामारीके तुरंत बाद एक अहम स्वास्थ्य मुद्देपर सर्वोच्च न्यायालयका दरवाजा खटखटाया जाना यह इंगित करता है कि किस हदतक कोई सरकारी नीति कारपोरेट ताकतसे जुड़ सकती है तथा आम नागरिकोंके लिए परेशानीका कारण बन सकती है। दवा उद्योग क्षेत्रका विकास तेजीसे हुआ है। भारतमें इस क्षेत्रका बाजार ५० अरब डालरके आसपास है। इसकी शक्ति और प्रभाव केवल भारतमें इसकी वृद्धिसे निर्धारित नहीं होती, बल्कि इसके वैश्विक विस्तारसे भी तय होती है। आधिकारिक आंकड़ोंके अनुसार बीते आठ सालोंमें दवाओंके निर्यातमें करीब दस अरब डालरकी वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप सरकारने इस क्षेत्रको बहुत महत्व दिया है। इस वर्ष मार्चमें तीन सालोंमें ५०० करोड़ रुपये प्रोत्साहनके रूपमें देनेकी घोषणा की गयी थी।

साथ ही यह भी सच है कि सरकार प्रमुख दवाओं और साजो-सामानकी कीमतें नियंत्रित रख पानेमें सफल रही है। हालमें जिस तरहसे वैश्विक निर्माताओं तथा भारतीय वितरकोंके भारी विरोधके बावजूद मेडिकल स्टेंटकी कीमतोंको नियंत्रित दायरेमें लाया गया, वह इस बातका उल्लेखनीय उदाहरण है कि सरकार ताकतवर समूहोंके सामने खड़ी हुई है। इसके बावजूद दवाओंकी मार्केटिंगमें जारी कदाचारसे मरीजोंकी परेशानी बनी हुई है तथा गलत, यहांतक कि आपराधिक रूपसे दवा उद्योग और चिकित्सक एवं अन्य लोग भारी कमाई कर रहे हैं। ऐसी स्थितिमें इस क्षेत्रको वैश्विक स्तरपर अधिक पेशेवर या प्रतिस्पर्धात्मक नहीं बनाया जा सकता है। यदि इस तरहके व्यवहारको इसी तरह चलने दिया गया तो इससे भारतकी साख गिरेगी तथा भारतीय कम्पनियोंके स्तरपर सवाल उठेंगे, जबकि दवा क्षेत्र किसी अन्य उद्योगसे कहीं अधिक नियमित रहा है। यदि समूचा देश एक भ्रष्ट आचरणको स्वीकार करता है और उसे जारी रहने देता है तो दूसरे क्षेत्रोंको भी कदाचार करनेका संकेत मिलेगा। यह स्तर बढ़ाने या अन्वेषण करने या बाजार बढ़ानेकी नयी रणनीति बनानेके लिए आदर्श स्थिति नहीं है। इस उद्योग और देशके सामने पहलेसे ही खुराक संबंधी अनेक जटिल समस्याएं और तमाम ब्रांडोंकी भीड़, जिनमेंसे कई ऐसी खुराकें बेचते हैं, जो या तो गैर-जरूरी हैं या वैश्विक बाजारमें प्रतिबंधित हैं, जैसी परेशानियां हैं। यह स्थिति नियंत्रणसे बाहर हो चुकी लगती है, विशेष रूपसे ब्रांडेड जेनेरिक दवाओंके मामलेमें। वर्ष २०२१ में भारतके प्रतिस्पर्धा आयोगने जानकारी दी थी कि अगस्त २०१९ और जुलाई २०२० के बीच दवा बाजारमें २८७१ फॉर्म्युलेशनके साथ ४७,४७८ ब्रांड जुड़े हुए थे, यानी इसका अर्थ यह है कि हर फॉर्म्युलेशनके लिए औसतन १७ ब्रांड उपलब्ध थे। ऐसी स्थितिमें कम्पनियों द्वारा दवा लिखनेके एवजमें इंसेंटिव देने तथा डाक्टरों द्वारा इसे लेनेको रोकनेके लिए एक कड़ा कानून बनानेके लिए दबाव बनाया जाना चाहिए। यह कानून एक ऐसे उद्योग क्षेत्रके लिए बेहतरीन दवा होगा, जिसके भविष्यको लेकर बहुत संभावनाएं हैं, परन्तु जिसके ऊपर कदाचारके कुछ ऐसे साये हैं, जिनपर गर्व नहीं किया जा सकता है।

आत्मबोध

वेदोंसे उत्पन्न

❒ स्वामी रामस्वरूप

वेदोंके ज्ञाता श्रीकृष्णने भगवदगीता श्लोक ३/१५ में दिया है कि हे अर्जुन! सभी कर्मोंको वेदोंसे उत्पन्न जानो और चारों वेद अविनाशी परमेश्वरसे उत्पन्न हुए हैं। जब ईश्वर सृष्टिका निर्माण करता है उस समय अमैथुनी सृष्टिके प्राणी होते हैं। उस समय कोई भी विद्वान अथवा गुरु आदि ज्ञान देनेवाला नहीं होता, सभी अज्ञानी होते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि बिना ज्ञान दिये ज्ञान नहीं होता। आज भी इस बातको बड़ी सरलतसे प्रायः गुरुजन अथवा अनादिकालसे चली आ रही परंपरागत भाषामें कह देते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं अथवा गुरु बिन गति नहीं। परंतु वेदोंके विद्वान ही जानते हैं कि यह तो वैदिक शिक्षा है कि जबतक ज्ञान दिया नहीं जायगा, तबतक ज्ञान नहीं होगा। तब हमें इस संसारके पदार्थों एवं ईश्वरका ज्ञान उस अमैथुनी एवं अज्ञानी सृष्टिमें किसने दिया। गीता सुनाते समय गीतामें कहे वैदिक व्याख्यानको अधिकसे अधिक विस्तार करके जनताको सुनायें। गीता एक वैदिक प्रवचन है। अतः स्वयं निराकार ब्रह्मने पृथ्वीके आरम्भमें मनुष्यको संपूर्ण सृष्टिके पदार्थों एवं ईश्वरके विषयमें चार वेदोंके रूपमें दिया। अतः हम वेदको ही प्रमाण मानें। यह भी स्पष्ट है कि यदि आपको कोई नहीं जानता तो आप उसको अपनी जानकारी देंगे। इसी आधारपर स्पष्ट है कि पृथ्वीके आरम्भमें ईश्वरको भी कोई नहीं जानता। स्वयं ईश्वरने अपना कर्म, स्वभाव एवं ज्ञान आदिका वर्णन वेदोंमें करके हमें समझाया है। अतः ईश्वरके स्वरूपको भी प्रथम हम केवल वेदोंसे ही जानें। जिससे आगे कभी भ्रांति नहीं होगी। मनुष्योंके बनाये हुए ईश्वरको मानना दुःखोंके सागरमें गोते खाना एवं झूठी तसल्ली प्राप्त करना है, जिससे हमें बचना चाहिए। अन्यथा भक्ति करेंगे और दुःखी रहेंगे। पुनः श्लोकके अर्थपर लौटते हैं। श्रीकृष्ण महाराजने श्लोक ८/२१में ईश्वरको अव्यक्त, अक्षर कहा है और इस अव्यक्त, अक्षर ईश्वरको प्राप्त करना ही श्लोकमें परम गति अर्थात सर्वोत्तम मोक्ष पद कहा है। यही मानव जातिका मुख्य लक्ष्य भी है। अब हम वेदोंके अनुसार श्लोक ८/२१ का दर्शन करें। ऋग्वेद मंत्र १/१६४/४६ में कहा कि अविनाशी ईश्वर एक है परन्तु योगीजन वेदोंके ज्ञाता विद्वान जन उसके अनंत नाम कहते हैं। इसी मंत्रमें ईश्वर अर्थात् निराकार ब्रह्मको मित्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम और वायु आदिके नामसे पुकारा है। इसी वेद मंत्रमें ईश्वरको अक्षर अर्थात् अविनाशी परमात्मा कहा है।

जनताको भ्रमित करता विपक्ष

❒ मिथिलेश झा

महंगीपर जिस प्रकारसे विपक्ष हमलावर है, वह उचित है या अनुचित। यह एक विचारणीय प्रश्न है। भारतकी आबादी १३० करोड़से ज्यादा है। इस आबादीमें ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझते हैं लेकिन बहुसंख्यक आबादी इससे अंजान रहती है कि देश दुनियाभरमें महंगीकी क्या स्थिति है। इसीको टारगेट करके विपक्ष अपना प्रचार-प्रसार शुरू करता है। जनता किसी तरहसे भ्रमित हो जाय और फिर इनके पालेमें आ जाय। यह एक ऐतिहासिक तथ्य भी है कि एक अच्छी सरकार जो देशको आर्थिक रूपसे मजबूत कर रही थी। उसे मात्र प्याजके दामपर सत्ताच्युत कर दिया गया। फिर २००४ से २०१४ के बीच अर्थव्यवस्थाकी बदहाली किसीसे छिपी नहीं है। आज भी विपक्ष पारम्परिक शैलीको अपनाये हुए है। वह आज भी चाहती है कि महंगीके मुद्देपर जनताको बरगला लिया जाय फिर सत्ताकी मलाई काटनेका अवसर मिल जाय। वर्तमान सत्ताके कार्यको समझनेवाले सात करोड़ युवा हैं। ये युवा मात्र चार-पांच वर्षोंमें शेयर बाजारसे जुड़ गये हैं। इनके पास ग्लोबल विजन है। इनको समझ है कि देश कहां जा रहा है। सोशल मीडियाने झूठके प्रचार-प्रसारका रास्ता बन्द कर दिया है। पहले जैसी स्थिति नहीं है कि मात्र अफवाह फैलाकर, नारा देकर चुनाव जीता जा सकता है।

महानताकी टैगिंग करके नोबेल प्राइज दिलवा कर भारतकी जनताको बरगलाया जा सकता है। पहले यह देखा गया कि जो देशकी अर्थव्यवस्थाको जिसने डुबाया वह भी महान अर्थशास्त्री कहलाया है। यह महानताको देखनेवाले मात्र बहुसंख्यक जनता रही है, जो अफवाहकी शिकार बन जाती थी। किन्तु अभी सात करोड़ युवा ऐसे हैं जो झूठके प्रचार-प्रसारका खण्डन डाटाके आधारपर कर देते हैं। इसको ऐसे कहिये देश जाग रहा है। यह जागरण आर्थिक क्षेत्रमें हो रहा है। महंगीका रोना विपक्ष लगातार कर रही है। महंगीका रोना जनताके बीच लगातार किया जा रहा है लेकिन यदि विपक्षके पास ऐसे ही नेता है जो आधी-अधूरी बात फैलाकर जनताको भ्रममें डालकर चुनाव जीतना चाहते हैं तो यह सोचना ही मूर्खता है। विश्वमें महंगीकी स्थिति क्या है यह भी देखना चाहिए। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकाकी बात बेइमानी है। इनका महंगीने बुरा हाल कर दिया है। जनता भीख मांगनेपर मजबूर है। रोटी कैसे मिलेगी इस बातपर आपसमें लड़ाई चल रही है। विकसित देशोंकी स्थिति देखते हैं। अमेरिकाका महंगी दर ९.५ के ऊपर है। ब्रिटेन दसके ऊपर है। पूरा यूरोप ११ प्रतिशतसे ऊपर है। अब भारतकी स्थिति सातके नीचे है। क्यों भाई भारतकी महंगी तो विपक्षको दिखता है लेकिन विश्वपटलपर महंगी रौद्र रूप धारण किये है यह नहीं दिखता है। अब बात है कि महंगी प्रबन्धनपर भारत सरकारकी प्रशंसा होना चाहिए या विरोध। जिस बातपर प्रशंसा होना चाहिए थी वहां महंगीकी बात प्रसार करके जनताको बरगलानेका अभियान चला रखा है। क्या यह सफल हो पायगा। निश्चित नहीं, क्योंकि वह सात करोड़ युवा विश्वपर टेलीस्कोपिक निगाह रखे हुए हैं। यह तुरन्त ही सोशल मीडियापर ऐक्टिव होकर दूधका दूध और पानीका पानी कर रहे हैं।

पेट्रोल-डीजलकी कीमतोंपर भी बीच-बीचमें आवाज उठायी जाती है। इसमें भी झूठका सहारा लिया जाता है। भारतमें आज भी रूस और यूक्रेन युद्धके पहले कीमतपर तेज मिल रहा है। अब दुनियाकी स्थिति यह है कि दुनियाभरमें युद्धके बाद पेट्रोल एवं डीजलकी कीमतें ५० प्रतिशतसे ज्यादा बढ़े हैं। यहांतक सऊदी अरबमें भी ८३-८१ रुपये लीटर पेट्रोलकी कीमत है। ऐसेमें भारतके प्रबन्धनका गुणगान होना चाहिए या जनताके बीच भ्रामक प्रचार। पेट्रोल-डीजलके प्रबन्धनका अमेरिका विरोध कर रहा है। यूरोप विरोध कर रहा है। यूक्रेन कहता भारतसे तेल नहीं यूक्रेनी खून खरीद रहा है। ऐसेमें विपक्षकी भूमिका क्या होनी चाहिए। विपक्षका सरकारके साथ खड़ा रहना चाहिए या जनताके बीच भ्रामक प्रचार। विपक्ष जब महंगी एवं बेरोजगारी मुद्दा उठाता है तो लगता है कि वह मात्र आज भी झूठका प्रचार करके जनताको बरगला कर चुनाव जीतना चाहता है। यह राष्ट्रहितमें नहीं है। यदि विपक्षके पास दूरदृष्टिका अभाव है तो उन्हें मौन रहना चाहिए। बोलकर वह अपनी स्थिति जनताके बीच हास्यास्पद बनाते जा रहे हैं। यदि सरकारकी नीतियोंमें कहीं कमी नजर आये तो उसके सुधारकी बात करनी चाहिए। सरकारको रास्ता बताया जाना चाहिए। साल-डेढ़ सालमें एक मुद्दा जरूर है लेकिन विपक्षको यह दिखता ही नहीं है कि इसपर बात करे।

एनसीएलटीसे जो कम्पनी नया प्रबन्धन लेता है, वह पुरान शेयर होल्डरका शेयर अपने पास ले लेता है। फिर कीमत बढ़ाकर नये निवेशकोंको थमा रहे हैं। यह मुद्दा अनुचित ही नहीं, बल्कि नये है। इनवेस्टरोंको लूटनेका रास्ता है। इसपर विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठाता है। कारपोरेटके खिलाफ मुंह खोलनेका साहस भी नहीं है, क्योंकि इसीसे चन्दा लेते हैं और फिर जनताको बरगलाकर सत्ता हथियानेका रास्ता तैयार करते हैं। विपक्ष मात्र आधा-अधूरा बात फैलाकर जनताको बरगला कर सत्ता पाना चाहती है। यह तरीका पुराना है। अब मात्र जनताको महंगीका रोना रोकर बरगलाया नहीं जा सकता है। नीतियोंकी गलतियोंमें सुधारका रास्ता तैयार करिये तभी कुछ हो सकता है।